आरक्षित

उत्तरधारा उच्च न्यायालय, नैनीताल

विशेष आवेदन संख्या 901/2018

नैनीताल बैंक लिमिटेड ..... अपीलकर्ता।

बनाम

मेसर्स नवीन किसान राइस मिल और अन्य। ..... प्रत्यर्थी(गण)

श्री राकेश थपलियाल, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री अतुल कुमार बंसल, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के विद्वान अधिवक्ता।

सुश्री प्रभा नैथानी, उत्तराधारा राज्य के विद्वान संक्षिप्त धारक/प्रतिवादी संख्या 5 से 7।

फैसला सुरक्षित:11.12.2018

निर्णय दिया गया:10.01.2019

1. (2014) 16 SCC 248
2. AIR 1969 SC 483
3. (2009) (106) RD 762
4. 2015 SCC OnLine Hyd 449
5. 2017 SCC OnLine Bom 9425
6. 2009 (6) Maharashtra Law Journal 977
7. (2011) 2 SCC 782
8. Writ Petition No. 10649 of 2017 dated 22.11.2017
9. (2013) 9 SCC 620
10. AIR 2015 Calcutta 282
11. AIR 2014 (NOC) 574 (Cal.)
12. Cases III (2009) BC 360
13. 2013 (4) Law Weekly 485
14. (2009) Banking Cases 145
15. AIR 1985 SC 218
16. (2014) 6 SCC 1
17. (1974) 4 SCC 98
18. AIR 1967 SC 295
19. AIR 2007 SC 1984
20. AIR 1962 SC 256
21. LR (1891) AC 107
22. (2002) 1 SCC 633
23. (2006) 12 SCC 607
24. (1964) 2 All ER 627
25. (1963) 1 SCR 1
26. (2007) 2 SCC 230
27. (1973) 1 SCC 216
28. 1958 SCR 360)
29. (1976) 1 SCC 77
30. (2002) 4 SCC 539
31. AIR 1957 SC 832

32. (2004) 9 SCC 686
33. (2004) 11 SCC 625
34. (1983) 2 SCC 235
35. AIR 2004 SC 4219
36. AIR 1963 SC 1241
37. 1947(49)BomLR 257
38. AIR 1964 SC 669
39. AIR 1992 SC 81
40. AIR 2005 SC 1090
41. AIR 1987 SC 1023
42. AIR 1956 SC 35
43. (2001) 5 SCC 175
44. AIR 1989 SC 836
45. (2016) 4 SCC 1
46. (2014) 5 SCC 610
47. AIR 2010 Bom 150
48. AIR 2011 Bom.163
49. AIR 2012 Guj 90
50. 1983 AIR 1246
51. (1972) 2 WLR 537
52. 2008 (110) Bom. LR 2880
53. (2003) 3 SCC 524
54. (2003) 6 SCC 675
55. (2006) 9 SCC 252
56. (2009) 8 SCC 366
57. (2012) 11 SCC 224
58. AIR 1997 SC 1125
59. (1998) 8 SCC 1
60. [1956] UKHL 2
61. [1974] 2 All ER 1128
62. (1980) 40 P&CR 336
63. 1996 SCC (1) 435
64. AIR 2007 SC 2414
65. AIR 2011 SC 1140
66. 2013 3 SCC 182
67. (1992) ILLJ 283 SC
68. 1997 1 SCC 9
69. 1997 (3) SCC 443

कोरमः **माननीय रमेश रंगनाथन, C.J।**

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

रमेश रंगनाथन, सी.जे.

यह अपील चौथे प्रतिवादी-बैंक द्वारा लिखित याचिका (एम/एस) सं. 2018 का 173 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 28.09.2018 पर रिट याचिका को अनुमति देने वाले आदेश से व्यथित है, जिसमें दिनांक 15.01.2018 के आदेश को रद्द करते हुए, दिनांक 15.01.2018 के उक्त आदेश के बाद बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के एक हिस्से को अमान्य घोषित करते हुए, यह निर्देश देते हुए कि सम्पति को उसकी स्थिति में बहाल विद्वान जाए जैसा कि दिनांक 15.01.2018 के विवादित आदेश को पारित करने से पहले था, और यह निर्देश देते हुए कि आदेश जिला मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार एक एक नया आदेश पारित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

2. इसमें प्रथम प्रतिवादी ने रिट याचिका (एम/एस) नं. 2018 का 173, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 14 (संक्षेप में "सरफेसी अधिनियम") दिनांक 09.10.2017 के से जारी किए गए नोटिस सरशियोरेराई करने और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.01.2018 में पारित आदेश सरशियोरेराई करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट की मांग करता है। 2017 का 51/66।

3. तथ्य, जहाँ तक आवश्यक है, यह है कि यहाँ अपीलकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के से एक नोटिस दिनांक 18.11.2016 को जारी किया, जिस पर प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 13 (3) के से अपनी आपत्तियाँ दिनांक 20.02.2017 दायर कीं। सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के से एक अधिकार नोटिस, अपीलार्थी-बैंक द्वारा 21.02.2017 पर जारी किया गया था, जिसने इसके बाद, 04.03.2017 पर प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर द्वारा 29.04.2017 29.04.2017 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व/वित्त), उधम सिंह नगर को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से से बैंक द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करने के लिए अधिकृत करते हुए एक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को सुनवाई और निपटारे के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व/वित्त), उधम सिंह नगर को स्थानांतरित कर दिया गया।संबंधित अधिकारी को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से मामलों धारा निपटने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से 4/5.5.2017 पर एक शपथ पत्र के साथ एक आवेदन किया गया था।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 09.10.2017 पर एक नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां दायर कीं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से 15.01.2018 पर एक आदेश पारित किया।

4. बैंक द्वारा जारी की जा रही बिक्री सूचना के अनुसार 13.07.2018 पर नीलामी आयोजित की गई थी, और नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले ने अपीलकर्ता-बैंक को बोली राशि का 25% का भुगतान किया था।इस न्यायालय न्यायालय द्वारा 19.07.2018 पर पारित यथास्थिति के आदेश के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने अभी तक उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि नहीं की है, न ही तिथि तक बिक्री-प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

5. अपील के से आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह था कि क्या जिला मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से एक व्यक्ति नामित था, और क्या कानून के से सम्पति के कब्जे के संबंध में आदेश पारित नहीं करने के लिए कोई विवेकाधिकार निहित था, सुरक्षित लेनदार द्वारा उसके सामने एक आवेदन भेजा जा रहा है, और क्या वह इन शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी या अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकता है।

6. सरफेसी अधिनियम की धारा 14 पर ध्यान देने पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि सुरक्षित लेनदार के साथ-साथ उधारकर्ता को सुनने के लिए ध्यान देंिस भेजने की पूरी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, बल्कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) द्वारा की गई थी; और राज्य सरकार ने अपने पूरक शपथ पत्र में, जिला मजिस्ट्रेट पारित पत्र की एक प्रति संलग्न की थी, जिन्होंने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से इन शक्तियों को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) को सौंप दिया था।दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा उद्धृत विभिन्न उच्च के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि इस पहलू पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के के विपरीत विचार थे; **सिद्धार्थ सरावगी** 1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ओर विधायी या अर्ध-न्यायिक शक्तियों के प्रत्यायोजन और दूसरी ओर प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के बीच अंतर करने के बाद कहा था कि विधायी शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं विद्वान जा सकता है और अर्ध-न्यायिक शक्तियों को भी आम तौर पर प्रत्यायोजित नहीं विद्वान जा सकता है; और प्रत्यायोजन मात्र प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में अनुमत था। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने

कि मात्र इसलिए कि कार्य, जो किसी विशेष नामित व्यक्ति को सौंपे विद्वान थे, कार्यकारी प्रकृति के हैं, इसका वास्तविक अर्थ अर्थ यह नहीं होगा कि इन शक्तियों को प्रत्यायोजित करने की कानूनी रूप से अनुमति है।

7 . विद्वान एकल न्यायाधीश ने अग्रेतर कहा कि 2013 में सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) में संशोधन किया गया था और चार प्रावधान जोड़े विद्वान थे; जिला मजिस्ट्रेटों या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों को कई पहलुओं की जांच की आवश्यकता थी जैसा कि सुरक्षित लेनदारों द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में संदर्भित किया गया था; इन दावों की सत्यता सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात ही, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अंततः कब्जे के लिए आदेश पारित कर सकते हैं; ऐसा नहीं था कि मात्र एक आवेदन दायर करके, सुरक्षित लेनदार कब्जे का आदेश प्राप्त कर सकता है; इस तरह के आदेश को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन में किए विद्वान दावों की सच्चाई को संतुष्ट करने के पारित करने की आवश्यकता थी। किसी अधीनस्थ अधिकारी या पुलिस को संपत्ति के कब्जे का अधिकार; हालाँकि, कब्जे के के लिए वास्तविक आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाना था, यद्यपि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने **हरि चंद अग्रवाल 2** पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिनियम की योजना को देखते हुए और शक्तियों की प्रकृति पर विचार करते हुए, विधानमंडल ने अपने विवेक से ये शक्तियां मात्र एक नामित व्यक्ति को दी थीं जो जिला मजिस्ट्रेट थे; इस प्रकार, ये शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दी जा थीं, क्योंकि यह मात्र उन्हीं पर थी कि ऐसी शक्ति प्रदान की गई थी; और ऐसा प्रतिनिधिमंडल कानून के अधिकार के बिना था, था, और इसका कोई कानूनी आधार नहीं था।इस पहलू पर कोलकाता और केरल उच्च न्यायालयों के फैसलों से सहमत होते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 09.10.2017 दिनांकित नोटिस और 15.01.2018 दिनांकित आदेश को अपास्त दिया।इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई।

9. अपीलकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश थपलियाल हमारा ध्यान उस दिनांकित कार्यवाही की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से बैंकों द्वारा दायर आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए अधिकृत किया था, ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि वर्तमान मामले मामले में, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 का धारा (1ए) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू नहीं किया गया है; क्योंकि "जिला मजिस्ट्रेट" में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 धारा 23 और धारा 14-ए को देखते हुए)। भूमि राजस्व अधिनियम), उसने मात्र सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से सुरक्षित लेनदार द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर किया था; ऐसी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास है और, किसी भी स्थिति में, उधारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से उपलब्ध के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; धारा 14 (1) के प्रावधान, और उप-धारा (1ए), अधिनियम सं। 2013 का 1; और चूंकि सुरक्षित परिसम्पतियों पर कब्जा करने का निर्देश देने देने का निर्णय लेने की शक्ति प्रशासनिक प्रकृति की है, इसलिए यह जिला मजिस्ट्रेट के लिए हमेशा खुला है कि वह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करे, और विषय सम्पति का कब्जा सुरक्षित लेनदार लेनदार को सौंप दे। विद्वान वकील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 और 23 पर भरोसा करेंगे; U.P की धारा 14-ए। भूमि भूमि राजस्व अधिनियम, 1901; और सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 3 (32), जो "मजिस्ट्रेट" को परिभाषित परिभाषित करती है। वह **इरशाद हुसैन 3; T.R पर भी भरोसा करेगा। ज्वैलरी 1; कैपिटल फर्स्ट 3; पूरन महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल; कनैयालाल लालचंद सचदेव 7; प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी '; और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक'।**

10. अपीलकर्ता प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री राकेश थपविद्वानल यह तर्क देने के लिए 'कनैयालाल लालचंद सचदेव' पर भी अवलम्ब रखेंगे कि याचिकाकर्ता के पास उक्त अधिनियम की धारा 14 के से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के से अपील दायर करके ऋण वसूली न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को लागू करने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है; और चूंकि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय है, इसलिए यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के के से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

11. अपीलकर्ता बैंक के विद्वान वकील श्री राकेश थपविद्वानल अग्रेतर प्रस्तुत करेंगे कि, मामले के किसी भी से, अपीलकर्ता-बैंक के कब्जे में लेने के कार्य द्वारा प्रथम प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया किया गया था; विषय सम्पति का भौतिक कब्जा जल्द से जल्द 22.05.2018 पर विद्वान गया था; विषय परिसर तब से अपीलकर्ता बैंक के कब्जे में है; प्रथम प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता ने उचित कानूनी कार्यवाही में चुनौती देने के लिए उक्त उक्त सम्पति की नीलामी के लिए जारी किए विद्वान नोटिस को अधीन नहीं किया है; और विद्वान एकल न्यायाधीश को यह निर्देश देना उचित नहीं था किनीलामी की कार्यवाही को अमान्य घोषित किया जाए।

12. उत्तराधारा राज्य की ओर धारा उपस्थित विद्वान संक्षिप्त धारक सुश्री प्रभा नैथानी, राज्य सरकार की ओर दायर पूरक शपथ पत्र पर अवलम्ब रखेंगी, ताकि यह प्रस्तुत विद्वान जा सके कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के दूसरे प्रावधान के से आदेश पारित करने की शक्ति मात्र एक प्रशासनिक शक्ति है, न कि चरित्र में न्यायिक; और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने में जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई कानूनी और वैध है।

13. दूसरी ओर प्रथम प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार बंसल प्रस्तुत करेंगे कि धारा 14 (1) और उप-धारा (1ए) के प्रावधान अधिनियम सं. 2013 का 1 मात्र एक उधारकर्ता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि धारा ; इसके संशोधन धारा पहले, अधिनियम सं। 2013 की धारा 1 में, दण्ड प्रक्रिया संहिता 14 में जिला मजिस्ट्रेट को आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी; जबकि दूसरा परंतुक अब जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आवेदनों के उद्देश्य के लिए, सुरक्षित लेनदार के पास उपलब्ध साक्ष्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए बाध्य करता है, उप-धारा (1ए) उधारा अपने अधीनस्थ अधिकारी संपत्ति और दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाती है; क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 14 (1) के से सुरक्षित लेनदार द्वारा किए विद्वान आवेदनों पर आदेश पारित पारित करने की आवश्यकता होती है, जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला नहीं है कि वह संपत्ति के कब्जे का निर्देश देने के लिए लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करे। भूमि राजस्व अधिनियम या सामान्य धारा अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता 14 (1) में उपयोग किए विद्वान "जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट" शब्दों को अलग अर्थ देने के लिए सहायता में नहीं लाया जा सकता है; और विद्वान एकल न्यायाधीश को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 15.01.2018 द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में उचित ठहराया गया था।

14. इस संबंध में प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार बंसल, **अरुपेश्वर चटर्जीत और अन्य 10 चेल्लापेरुमल और अन्य 11 सुंदरम बीएनपी परिबास होम फाइनेंस 12, के. अरोकियाराज 13; और असीना 14** पर भरोसा करेंगे। वह यह प्रस्तुत करने के लिए **हरि चंद अग्रवाल 2** पर भी भरोसा करेंगे कि यह मात्र तभी हो सकता है जब जब अधिनियम प्रत्यायोजन की शक्ति प्रदान करता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।उन्होंने **मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश 15** का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूंकि किसी निर्णय को क़ानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) की भाषा के रूप में, इसके प्रावधान और धारा 14 (1ए) स्पष्ट और स्पष्ट हैं, इसलिए उस पर रखे जाने वाले निर्माण पर न्यायालयों के किसी भी निर्णय पर अवलम्ब करना अनावश्यक है; प्रावधान स्वयं स्पष्ट रूप धारा दर्शाते हैं किइस तरह का आदेश पारित करने की शक्ति मात्र जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है; आदेश पारित करने के लिए अकेले उधारा आवश्यक है; और वह इधारा किसी अन्य अधिकारी को सौंप नहीं सकता है।

15. प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अतुल कुमार बंसल, **हर्षद गोवर्धन सोंडागर 16** पर यह प्रस्तुत प्रस्तुत करने के लिए अवलम्ब रखेंगे कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के के से, मात्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से कार्यवाही में सवाल उठाया जा सकता है, न कि सरफेसी अधिनियम की की धारा 17 के से; और चूंकि एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए पहले प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता को अधिकार था कि इस न्यायालय से संपर्क करें।

I. प्रासंगिक वैधानिक

15. सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने का प्रावधान है, और, इसकी उप-धारा (1) के से, जहां किसी भी सुरक्षित संपत्ति का का कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाना आवश्यक है, या यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के से सुरक्षित संपत्ति में धारा धारा किसी को भी सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, तो सुरक्षित लेनदार, ऐसी किसी भी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के उद्देश्य धारा , मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसी कोई सुरक्षित संपत्ति या उसधारा संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित या पाए जा सकते हैं, धारा लिखित रूप रूप में अनुरोध कर सकता है, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, उसका कब्जा लेने के लिए।

16. सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के पहले परंतुक में कहा गया है कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी आवेदन के साथ एक शपथ पत्र होगा, जिधारा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि की जाएगी, जिसमें घोषणा की जाएगी कि (i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दायर करने की तिथि तक बैंक का कुल दावा; (ii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है, बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर वैध और स्थायी स्थायी प्रतिभूति ब्याज धारण कर रहा है, और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा सीमा अवधि के भीतर है; (iii) उधारकर्ता ने ने उपरोक्त उपधारा (ii) में व्यतिक्रम संपत्तियों का विवरण देते हुए विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है; (iv) इस इस तरह के व्यतिक्रम के परिणामस्वअभ्यावेदन, वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में, उधारकर्ता के खाते को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के अभ्यावेदन में वर्गीकृत किया गया है; (vi) यह पुष्टि करते हुए कि धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक साठ दिनों की अवधि के नोटिस की अवधि, व्यतिक्रम वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग करते हुए, उधारकर्ता पर लागू कर दी गई है; (vii) उधारकर्ता धारा प्राप्त नोटिस के जवाब में आपत्ति या अभ्यावेदन, सुरक्षित लेनदार द्वारा विचार किया गया है, और ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन को स्वीसेर नहीं करने के सेरणों को उधारकर्ता को सूचित सूचित कर दिया गया है; (viii) उधारकर्ता ने उपरोक्त नोटिस के बावजूद वित्तीय सहायता से कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है और अधिकृत अधिसेरी है

17. धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि, अधिकृत अधिकारी धारा शपथ पत्र प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, शपथ पत्र की सामग्री को संतुष्ट करने के पश्चात आवेदन तिथि धारा तीस दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य धारा उपयुक्त आदेश पारित करेगा।धारा 14 (1) के तीसरे परंतुक में कहा गया है कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण के बाद कारणों के लिए तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वह इसके लिए लिखित कारण दर्ज करने के पश्चात ऐसी अग्रेतर की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कुल साठ दिनों दिनों धारा अधिक नहीं।धारा 14 (1) के चौथे परंतुक में कहा गया है कि पहले परंतुक में उल्लिखित शपथ पत्र दाखिल करने करने की आवश्यकता, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को किसी भी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

18. धारा 14 (1 -ए) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को (i) ऐसी संपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे कब्जे में लेने के लिए; और (ii) ऐसी संपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य धारा , मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐधारा कदम उठा सकते हैं उठा सकते हैं और ऐधारा बल का उपयोग या उपयोग करा सकते हैं, जो उनकी मत में आवश्यक हो। सरफेसी अधिनियम

की धारा 14 (3) में कहा गया है कि इस धारा के अनुसरण में किए गए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट और और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी के किसी भी कार्य पर किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

19. जबकि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के पहले तीन प्रावधान 2013 के अधिनियम 1 जो कि W.E.F 15.01.2013 द्वारा जोड़े गए थे। दूसरे परंतुक में "आवेदन की तिथि धारा 30 दिनों की अवधि के भीतर" शब्द, और चौथे परंतुक, 2016 के अधिनियम 44 W.E.F 01.09.2016 द्वारा जोड़े गए थे। उप धारा (1 -ए) धारा 14 में अंतःस्थापित किया किया गया था, और शब्द "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी" 2013 के अधिनियम 1 द्वारा W.E.F 15.01.2013 धारा 14 की उप-धारा (3) में अंतःस्थापित किए गए थे। ।

II. जिला मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र की सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात धारा 14 के से आवेदन पर एक आदेश पारित करना आवश्यक हैः

20. उधारकर्ता के हित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में संशोधन किए गए थे। इन इन प्रावधानों में कहा गया मात्र कि एक सुरक्षित लेनदार जो धारा 14 के से मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप की मांग कर रहा मात्र, उधारा पहले परंतुक के विभिन्न उपखंडों (i) धारा (ix) के से विचार की गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक हलफनामा हलफनामा दायर करना आवश्यक मात्र और जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र की सामग्री धारा संतुष्ट होने के पश्चात ही सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए बाध्य करता मात्र।**(स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अन्य अन्य। ")**।

21. अधिकृत अधिकारी किसी पट्टेदार को बलपूर्वक बेदखल नहीं कर सकता है, और उधारा एक शपथ पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 के से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए।इसके पश्चात मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना चाहिए और कथित पट्टेदार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सुरक्षित लेनदार को सुनने के बाद निर्णय लेना चाहिए।धारा 14 में निर्दिष्ट प्राधिकरण, मात्र यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि धारा 13 (2) के से एक नोटिस जारी किया गया था और सम्पति के साथ आगे बढ़ना एक सुरक्षित सम्पति है, मात्र अपने माध्यम धारा या अपने अधीनस्थ व्यक्ति के माध्यम धारा अपनी सम्पति को सुरक्षित करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करता है।**(हर्षद गोवर्धन सोंडागर 16**)।

22. जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट शपथ पत्र की सामग्री से संतुष्ट होने के पश्चात ही सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए बाध्य मात्रं।धारा 14 (1) के दूसरे परन्तुक के से अनुध्यात मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि वह इस तरह के शपथ पत्र में किए गए दावों की तथ्यात्मक शुद्धता की जांच करे, लेकिन लेन-देन की कानूनी विशेषताओं की नहीं।मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि दर्ज करने के पश्चात ही सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता मात्र।**(स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 9)**।जहां सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 14 के से सीधे उसधारा संपर्क करता है, मजिस्ट्रेट धारा 14 में प्रदान किए गए आवेदन की जांच करेगा करेगा और फिर, यदि संतुष्ट हो जाता है, तो एक अधीनस्थ अधिकारी को, जैसा कि धारा 14 (1) (ए) के से प्रदान किया गया गया है, संपत्ति और दस्तावेजों का कब्जा लेने और उन्हें सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए अधिकृत करेगा। उस उद्देश्य के के लिए मजिस्ट्रेट संबंधित अधिकारी को ऐसे बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है जो आवश्यक हो।कब्जा हो।कब्जा लेने पश्चात परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को भेज दिया जाएगा।**(स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक9)**।

III. क्या डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट उस शक्ति को हटा सकता है, जिसे धारा 14 (1) के दूसरे प्रावधान के से अतिरिक्त डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट को पारित करने का आदेश दिया गया है?

23. प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता की ओर धारा आग्रह किया विद्वान तर्क, जिधारा विद्वान एकल न्यायाधीश का पक्ष पक्ष मिला, यह था कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से आदेश

आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 14 के से बैंकों के आवेदनों का निपटान करने के लिए अधिकृत किया था। दिनांकित दिनांकित 29.04.2017 आदेश इस प्रकार हैः

"अदालत कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर

पत्र सं (188411) रीडर-2017 तिथि-29 अप्रैल, 2017

<u>आदेश</u>

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से बैंकों के आवेदन के निपटारे के लिए आदेश, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व/वित्त) उधम सिंह नगर इसके द्वारा अधिकृत हैं।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित आवेदन को सुनवाई/निपटान के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व/वित्त) उधम सिंह नगर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

संबंधित अधिकारी (अभिलेख), उधम सिंह नगर को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि कानूनी कानूनी सलाह के पश्चात सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के से मामलों को निपटाने के लिए सी. आर. ए. पाताल धारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व/वित्त) उधम सिंह नगर को उपलब्ध कराया जाएगा।

तिथि- 29 अप्रैल, 2017

एस. डी.

(डॉ. नीरज खैरवाल)

कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट

उधम सिंह नगर "

24. इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या जिला मजिस्ट्रेट, सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को दिनांकित 29.04.2017 के आदेश के माध्यम धारा अपनी शक्तियां सौंप सकता था, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 (1) मात्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को को संदर्भित करती है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नहीं।जब उसने परंतुक और उप-धारा अंतःस्थापित की (1 -ए) 2013 के अधिनियम 1 15.01.2003 द्वारा धारा 14 तक। संसद इस बात अवगत थी कि कि उक्त संशोधन के पहले, उसने धारा 14 (1) के से मात्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान थी। संसद ने, तब भी, दूसरे परंतुक के से, मात्र जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को, सुरक्षित परिसंपत्तियों का का कब्जा लेने के उद्देश्य से, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए शपथ पत्र के साथ, सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए चुना है, न कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को।

25. प्रावधानों को शामिल करने से पहले, 2013 के अधिनियम 1 द्वारा W.E.F. 15.01.2013, सुरक्षित लेनदार किए गए आवेदन के साथ सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए शपथ पत्र की न तो कोई आवश्यकता थी, न ही जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए शपथ पत्र की सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त पारित करने की आवश्यकता थी। 2013 के अधिनियम 1 द्वारा धारा 14 धारा धारा 14 (1) और धारा 14 धारा उप-धारा (1ए) में पहले तीन प्रावधानों को शामिल करने के साथ। 15.01.2013, संसद ने सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर एक आदेश पारित करने और परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेने और उन्हें सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित अग्रेषित करने के परिणामी कार्य को अलग कर दिया है।2013 के अधिनियम 1संख्या 1 द्वारा W.E.F.15.01.2013 धारा 14 (1) में पहले और दूसरे प्रावधानों को शामिल करने का परिणाम।, जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को

अब शपथ पत्र की सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

26. धारा 14 की उप-धारा (1ए) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को दूसरे परंतुक के से आदेश पारित करने की शक्ति सौंपने के लिए अधिकृत नहीं करती है, पहले परंतुक के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र की की सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी पर।जबकि दूसरे परंतुक के से आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, वह भी, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए शपथ पत्र की सामग्री के बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात यह मात्र परिणामी कार्य है, जो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित का पालन करता है, जिसे उनके द्वारा उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को सौंपा जा सकता है, न कि आदेश पारित करने करने की शक्ति।भले ही आदेश, जिसे दूसरे परंतुक के से पारित किया जाना आवश्यक है, को चरित्र में प्रशासनिक माना जाता है, इस तरह के प्रशासनिक आदेश को पारित करने की शक्ति संसद द्वारा मात्र जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है, और कोई और नहीं।

27 " ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में "डेलिगेशन" को "दूसरे को एक एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त सशक्त बनाकर अधिकार सौंपने का कार्य" के रूप में परिभाषित किया गया है।पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन में "प्रतिनिधि मंडल" को "प्रतिनिधि बनाने या नियुक्त करने के कार्य" के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रत्यायोजन, आम तौर पर, प्रतिनिधि मंडल को अनुदान देने वाले व्यक्ति द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन इसका अर्थ उन चीजों करने का अधिकार प्रदान करना भी है जो अन्यथा उस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता।**(सिद्धार्थ सरावगी 1)**।प्रत्यायोजन को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में रहने वाली शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को सौंपने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रतिसंहरण या संशोधन की पूरी शक्ति अनुदानकर्ता या प्रतिनिधि के पास शेष है।प्रत्यायोजन में अक्सर दूसरे को विवेकाधीन अधिकार देना शामिल होता है, है, लेकिन ऐसा अधिकार विशुद्ध रूप से व्युत्पन्न होता है।अंतिम शक्ति हमेशा प्रतिनिधि के पास रहती है और कभी उसका त्याग नहीं किया जाता है।**(ग्वालियर रेयॉन रेशम निर्माण (डब्ल्यू. वी. जी.) कं. लिमिटेड "; सिद्धार्थ सरावगी 1)**

28. प्रतिनिधि गैर-संभावित प्रतिनिधि का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि के पास प्रत्यायोजित करने की कोई शक्ति नहीं है।उक्त उक्ति किसी अधिनियम या किसी प्राधिकरण को प्रदान करने वाले अन्य साधन के निर्माण के नियम को इंगित करती करती है।आम तौर पर, किसी भी प्राधिकरण को किसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग उस प्राधिकरण द्वारा द्वारा किया जाना है, और किसी अन्य द्वारा नहीं।लेकिन अधिनियम की भाषा, दायरे या उद्देश्य में किसी भी विपरीत संकेत से इरादे को नकार दिया जा सकता है।(**बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और Anr.18 ; सिद्धार्थ सरावगी 1**)।विधायिका आवश्यक विधायी कार्यों को सौंप नहीं सकती है जिसमें विधायी नीति का निर्धारण या चयन और औपचारिक रूप से उस नीति को आचरण के बाध्यकारी नियम में लागू करना शामिल है।विधानमंडल द्वारा आवश्यक विधायी कार्यों के निष्पादन और मार्गदर्शक नीति निर्धारित करने पश्चात विधानमंडल कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को कोई भी सहायक या अधीनस्थ शक्तियां सौंप सकता है जो अधिनियम की नीति और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं।पूर्ण विधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित विनियम, आम तौर पर एक निर्दिष्ट प्राधिकरण को सौंपा गया कार्य होता है।प्रत्यायोजित शक्ति के सीमा और विस्तार को समझने में, प्रतिनिधि के आवश्यक और गैर-आवश्यक कार्यों के बीच के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।जबकि किसी भी आवश्यक कार्यों का उप-हस्तांतरण नहीं हो सकता है, प्रतिनिधि मंडल मंडल के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त आदेश के लिए, गैर-आवश्यक कार्यों को प्रतिनिधि के अधिकार और पर्यवेक्षण के से निष्पादित आदेश के लिए उप-निर्दिष्ट किया जा सकता है। चूँकि विधानमंडल को कानून के कार्यान्वयन पर विवरण तैयार करने के लिए अपना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह उक्त कार्य किसी एजेंसी को सौंप सकता है।वह एजेंसी अपने अधीनस्थों को ऐसा कार्य नहीं सौंप सकती क्योंकि यह प्रतिनिधि पर रखे गए विश्वास का भंग होगा।(**सिद्धार्थ** होगा।(**सिद्धार्थ सरावगी 1)**।

29. **सुंदरम बी. एन. पी. परिबास होम फाइनेंस लिमिटेड 12** में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 14 के से वैधानिक शक्ति का भंडार, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जैसा भी मामला हो; सर्फेसी अधिनियम, सशक्त अधिनियम, उस वैधानिक शक्ति के प्रत्यायोजन को अधिकृत नहीं करता है; इसके बिना, उस वैधानिक शक्ति के भंडार को उस शक्ति का प्रयोग करना होगा और राहत को अपने नियंत्रण में करना होगा; जिधारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है; वह ऐधारा उद्देश्य के लिए, एक आयोग जारी कर सकता है, यहां तक कि आधिकारिक पदानुक्रम में एक अधीनस्थ को भी, पर्यवेक्षण करने के लिए, या/और अग्रेतर की कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल को अधिकृत कर सकता है; है; लेकिन, यह मात्र उसके नियंत्रण और आदेशों के से हो सकता है।

30. उप-धारा द्वारा प्रदत्त प्रत्यायोजन धारा विशिष्ट शक्ति (1 -(क) धारा 14 की धारा के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मात्र अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को उसधारा संबंधित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए अधिकृत करना है।जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को, दूसरे परंतुक के से, पहले परंतुक के संदर्भ में, सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्ति, उप-धारा (1 -(क) संसद द्वारा किसी अन्य अधिकारी प्रत्यायोजित किए जाने की अनुमति दी गई।यदि संसद जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ किसी अधिकारी को भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करने का इरादा रखती है, तो वह धारा 14 की उप-धारा (1ए) में इस प्रकार निर्दिष्ट होती और किसी अधीनस्थ अधिकारी को मात्र संपत्ति और दस्तावेजों का कब्जा लेने और ऐसी संपत्ति और और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति को सीमित नहीं करती। संसद द्वारा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से एक आदेश पारित करने के लिए अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने का अधिकार प्रदान करने की अनुपस्थिति में में, प्रत्यायोजन गैर-शक्तिशाली प्रत्यायोजन का सिद्धांत लागू होगा, और ऐसा कोई भी प्रत्यायोजन तब धारा 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, और अवैध होगा।

IV. किसी वैधानिक प्रावधान में शब्दों को जोड़ना अस्वीकार्य है।

31. अपीलार्थी-प्रत्यर्थियों द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 पर रखे गए निर्माण को स्वीकार करने के लिए, धारा 14 (1) और इसके दूसरे परंतुक में "अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट" शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता होगी।उपयोग की गई भाषा के स्वाभाविक अर्थ के अनुसार एक प्रावधान का अर्थ लगाया जाना चाहिए।अतः न्यायालय को किसी अधिनियम अधिनियम की व्याख्या करते समय ऐसे शब्दों को जोड़ने की कोशिश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए जो अधिनियम में नहीं नहीं पाए जाते हैं।**(दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड 19 ; मोहिंद्रा सप्लाई Co.20; बैंक ऑफ इंग्लैंड 21; अंजुम M.H। घवाला 22; जे. श्रीनिवास राव 23)**। वैधानिक भाषा को हमेशा अनुमानित रूप से सबसे स्वाभाविक और सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो (**चेर्टसे अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 24)।**जब भाषा सरल और असंदिग्ध होती है, और मात्र एक ही अर्थ को स्वीकार करती है, तो क़ानून के निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अधिनियम अपने लिए बोलता है।अर्थ विधायिका के व्यक्त इरादे से एकत्र किया जाना चाहिए।**(डॉ. विजय आनंद महाराज 25)।**

32. एक वैधानिक प्रावधान के अर्थ में, निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम शाब्दिक निर्माण है।अदालत को बस यह देखना है कि वह प्रावधान क्या कहता है। यदि प्रावधान स्पष्ट है और यदि उस प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो न्यायालय को क़ानूनों के निर्माण के अन्य नियमों **(रघुनाथ राय बरेजा 26; हीरालाल रतनलाल 27)** की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, और न ही अदालतों के लिए इस आधार पर कोई अन्य काल्पनिक निर्माण अपनाने के लिए खुला होगा कि ऐसा काल्पनिक निर्माण अधिनियम के कथित उद्देश्य और नीति के साथ अधिक सुसंगत है। **(कनई लाल सूर 28)**, **28)**, क्योंकि यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि उपयोग की जाने वाली भाषा मन को बोलती है और निर्माताओं के इरादे को प्रकट करती है।**(T.V। सुंदरम अयंगर (पी) ltd 29)**। ऐसा माना जाता है कि विधायिका ने कोई गलती नहीं की है और जो उसने कहा है उसे कहने का इरादा है।यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष है,

न्यायालय इस कमी को ठीक या पूरा नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब इसका शाब्दिक अध्ययन एक बोधगम्य परिणाम देता है।**(रघुनाथ राय बरेजा 26; ओमबालिका दास 30; सोडरा देवी 31; प्रकाश नाथ खन्ना 32; दिल्ली वित्तीय निगम33)**। छिपे हुए अर्थ का पता लगाने के लिए निर्माण की किसी भी बाहरी सहायता को बुलाना अस्वीकार्य होगा।**(D.D। जोशी 34)**। जहाँ किसी क़ानून के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहाँ शाब्दिक अधिनियम के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।**(स्वीडिश मैच एबी 35; रघुनाथ राय बरेजा 26)**।सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) और इसके दूसरे परंतुक की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है।इसलिए, इसके अर्थ को समझने के लिए बाहरी सहायता का सहारा लेना अनावश्यक है, जैसे कि अन्य अधिनियमों के प्रावधान।

V. विधानमंडल के इरादे का पता धारा 14 के अन्य खंडों के पठन धारा लगाया जाना चाहिए, न कि मात्र दूसरा परंतुकः

33. न्यायालय को न मात्र अर्थ लगाए जाने वाले खंडों पर बल्कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करके विधायिका के इरादे का पता लगाना चाहिए।इसे कानून के अन्य भागों के साथ धारा की तुलना करनी चाहिए, और उस सेटिंग में जिसमें धारा की व्याख्या की जानी है। **(W.B राज्य बनाम वी.भारत संघ36; बॉम्बे प्रांत 37; ओकारा अनाज खरीदारों का सिंडिकेट Ltd.38; R.S. रघुनाथ 39;** और **माणिक लाल मजूमदार40)**। अधिनियम के किसी भी हिस्से और अधिनियम के किसी भी शब्द को अलग से नहीं लिया जा सकता है।क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो। **(R.S. रघुनाथ 39; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 41)।**

34. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम सरफेसी अधिनियम की धारा 14 की विभिन्न उप-धारा ओं, ओं, प्रावधानों और खंडों की जांच करें। धारा 14 (1ए) के धारा (1) और (2) सरफेसी अधिनियम म की धारा 14 (1) के धारा (ए) और (बी) के साथ समान सामग्री में हैं। परिणामस्वरूप, धारा 14 में उप-धारा (1ए) को शामिल करने पर, धारा धारा 14 (1) के से जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में में लेने और ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने की शक्ति अब जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को सौंपी जा सकती है, और परिणामस्वरूप ऐसी शक्ति का उपयोग अब जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जब वे जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किए जाते हैं।

35. धारा 14 (3), 2013 के अधिनियम 1 द्वारा इसके संशोधन धारा पहले 15.01.2013 धारा प्रभावी, यह निर्धारित किया गया था कि धारा 14 के अनुसरण में किए गए जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के किसी भी कार्य पर किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। संशोधन के परिणामस्वरूप, उप-उप-धारा (3) में "**मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी**" शब्द जोड़े गए हैं।चूँकि हैं।चूँकि संसद ने उपरोक्त शब्दों को मात्र उप-धारा (3) में डाला है, और धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक में ऐसा निर्धारित नहीं किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से आदेश पारित करने की शक्ति मात्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है, न कि किसी अन्य अधिकारी को।जब एक अधिनियम में अलग-अलग-अलग महत्व के शब्दों का उपयोग लगातार दो प्रावधानों में किया जाता है, तो यह बनाए रखना मुश्किल होगा कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, और निष्कर्ष यह होना चाहिए किदोनों अभिव्यक्तियों के अलग-अलग अर्थ हैं। हैं। **(आर्थर पॉल बेंथल 42)**। जब विधायिका ने विभिन्न उप-खंडों में विभिन्न वाक्यांशों का उपयोग करने का ध्यान रखा है, है, तो आम तौर पर विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को अलग-अलग अर्थ दिए जाने की आवश्यकता होती है।**(आर्थर पॉल बेंथल 42; हंसराजभाई वी. कोडाला 43)**।यदि विधायी इरादा अंतर नहीं करना था, और "जिला मजिस्ट्रेट" कहते समय इसका उद्देश्य "अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट" या किसी अधीनस्थ अधिकारी को शामिल करना था, तो स्थिति को अलग तरह से व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।जब स्थिति को अलग तरह से व्यक्त किया गया है तो

विधायिका को एक अलग इरादे को व्यक्त करने का इरादा रखने के लिए लिया जाना चाहिए।**(सी. आई. टी. बनाम पूर्व पश्चिम आयात और निर्यात (पी) ltd 44)**

VI. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताकारों द्वारा दिए गए निर्णयः

36. यह मात्र तभी है जब "जिला मजिस्ट्रेट" या "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" शब्दों को एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शामिल करने के लिए माना जाता है, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग जा सकता है।यह जाँचने से पहले कि क्या इस तरह का निर्माण करने की अनुमति है, आइए अब हम दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों ध्यान दें दें।

37. **T.R. ज्वेलरी4**, हैदराबाद में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 मात्र मुख्य मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भित करती है; यदि वास्तव में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के के समक्ष कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती, तो विधानमंडल जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ऐसी संपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेने और ऐसी संपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए अधिकृत करने की अनुमति नहीं देता; यह तर्क कि धारा 14 (1ए) में प्रतिनिधिमंडल मात्र मात्र मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आदेश के निष्पादन के संबंध में है, और आदेश पारित नहीं करने के संबंध में है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है; धारा 14 (1) (ए) और (बी), जो इसधारा संबंधित है।

38. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों धारा संबंधित है और इसकी उप-धारा (1) के से, प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, राज्य सरकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में उतने व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है जितना वह उचित समझे और उनमें धारा एक को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगी।उसकी उप-धारा से तहत, राज्य सरकार एक उप-मंडल से प्रभारी से रूप में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है और उसे अवसर की आवश्यकता से अनुसार प्रभार से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार एक उप-मंडल से प्रभारी मजिस्ट्रेट को मंडल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा।से (4 -क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, उप-धारा (4) के से अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है।

39. सी. आर. पी. सी. की धारा 23 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता से संबंधित है और इसकी उप-धारा (1) के से, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अलावा सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। धारा 23 (2) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर अपने अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच व्यवसाय के वितरण और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को व्यवसाय के आवंटन के बारे में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

40. इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 और 23 के प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों में पढ़ा जा सकता है, यह ध्यान दें उपयोगी है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 35 में निर्धारित किया गया है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या धारा किसी कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है। सरफेसी अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि अन्य अधिनियमों का लागू होना वर्जित नहीं है और इसके तहत, सरफेसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

41. सरफेसी अधिनियम की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए, यदि सरफेसी अधिनियम में कोई प्रावधान है, और यदि यदि किसी अन्य कानून में कोई प्रावधान है जो उस धारा असंगत है, तो सरफेसी अधिनियम के प्रावधान का प्रभाव होगा न कि किसी अन्य कानून के प्रावधान का। **(हर्षद गोवर्धन सोंडागर16)**। धारा 37 में निर्दिष्ट पहले तीन अधिनियम आम तौर पर प्रतिभूतियों धारा संबंधित हैं और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली धारा संबंधित है। सरफेसी अधिनियम की धारा 41 तीन अधिनियमों- कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में संशोधन करती है।मात्र पहले दो अधिनियम धारा 37 में शामिल हैं, न कि तीसरे i.e में। बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985।**(मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और अन्य 45)**। धारा 37 का प्रभाव यह है कि उक्त अधिनियम के से शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में सरफेसी अधिनियम के से निहित प्रावधानों के अलावा, एक पक्ष के आदेश धारा 37 में उल्लिखित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंक और वित्त संस्थान संस्थान अधिनियम, 1993, या उस समय लागू किसी अन्य कानून की वसूली धारा पीछे हटना उचित होगा।**(मैथ्यू वर्गीज46)**

42. न तो धारा 35 और न ही सरफेसी अधिनियम की धारा 37 दूसरे के अधीन है।यदि धारा 37 में "या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून" का शाब्दिक अर्थ दिया जाता है, तो धारा 35 पूरी तरह धारा अनुचित हो जाएगी क्योंकि अन्य सभी कानून तब सरफेसी अधिनियम के अतिरिक्त होंगे और उसका अपमान नहीं करेंगे। धारा 35 में यह प्रावधान करने के पश्चात कि सरफेसी अधिनियम उन सभी अन्य कानूनों पर प्रबल होगा जो इसके साथ असंगत हैं, यह संसदीय इरादा नहीं हो सकता था।दोनों स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी खंडों को दोनों को अर्थ देकर सबसे अच्छा सामंजस्य बनाया सकता है।यह मात्र धारा 37 में निहित "या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून" अभिव्यक्ति के दायरे को सीमित करके किया जा सकता है।इसलिए इस अभिव्यक्ति का अर्थ मात्र प्रतिभूति बाजार से संबंधित अन्य कानूनों से होना चाहिए, क्योंकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, सरफेसी अधिनियम के अलावा, बैंकों और और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित एकमात्र अन्य विशेष कानून है।**(मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड 45)। 45)।** जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 37 में उपयोग किए गए "या कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून" शब्दों शब्दों का अर्थ मात्र प्रतिभूति बाजार धारा संबंधित अन्य कानून हैं, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता ऐसी नहीं है, हैदराबाद हैदराबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने T.R में कहा। ज्वैलरी 4 ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को धारा 37 के दायरे में आने वाले कानूनों में धारा एक मानते हुए त्रुटि की थी। अपीलार्थी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश थपलियाल **T.R. ज्वेलरी** पर अवलम्ब रखा गया। इसलिए एसका कोई लाभ नहीं है। यह मत व्यक्त किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, संहिता, 1973 की धारा 20 के अनुसार, राज्य सरकार जितने व्यक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है और उनमें धारा एक को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगी; धारा 20 की अग्रेतर की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐधारा मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता या किसी अन्य कानून के से जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जा सकती हैं; इस प्रकार एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को उन सभी शक्तियों का प्रयोग का अधिकार है जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित दंड प्रक्रिया संहिता के से जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान की जाती हैं; धारा 23 सी. आर. पी. सी. के खाली पढ़ने धारा पता चलेगा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इसके अधीन नहीं है।

43. **प्रफुल्ल कुमार 8** में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय; संशोधन पहले, मात्र जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार था; हालाँकि, संशोधन के पश्चात उप-धारा (1ए) डाली गई है; यद्यपि, उक्त उप-धारा द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार है।

44. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है धारा 20 (2) Cr.P.C। यह निर्धारित करता है कि एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता के से या उस समय लागू किसी अन्य कानून के से जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाएं।सर्फेसी अधिनियम की धारा 37 में "कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून" शब्द मात्र प्रतिभूति बाजारों धारा संबंधित कानूनों धारा संबंधित हैं, और इसमें Cr.P.C के प्रावधान शामिल नहीं होंगे। अपीलार्थियों की ओर धारा **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 47** पर रखी गई अवलम्ब का भी कोई फायदा नहीं है।

45. **इरशाद हुसैन 3** में, जिस पर अपीलकर्ता की ओर धारा अवलम्ब रखी गई है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि U.P की धारा 14A को देखने के बाद। भूमि राजस्व अधिनियम, 1901, अतिरिक्त कलेक्टर के पास कलेक्टर के समान शक्ति है और इस प्रकार कलेक्टर में अतिरिक्त कलेक्टर शामिल होता है।U.P की धारा 14A। भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों धारा संबंधित है और इसकी उप-(1) के से राज्य सरकार किसी जिले में या दो या दो धारा अधिक जिलों में संयुक्त रूप धारा एक अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है।उप-धारा (2) से तहत, एक अतिरिक्त कलेक्टर राज्य सरकार की इच्छा से दौरान अपना पद संभालेगा।उप-धारा (3) से तहत एक अतिरिक्त कलेक्टर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे मामले या मामलों से में कलेक्टर से ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो संबंधित कलेक्टर निर्देशित करे।उप-धारा (4) के से, यह अधिनियम और और कलेक्टर से लागू होने वाला हर अन्य कानून प्रत्येक अतिरिक्त कलेक्टर से लागू होगा, जब वह उप-धारा (3) के से किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करता है, जैसे कि वह जिले का कलेक्टर हो। धारा 14-ए (3) के से अतिरिक्त कलेक्टर जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, वे <आईडी1> के से कलेक्टर की शक्तियां हैं। राज्य विधानमंडल के लिए भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 और न कि सरफेसी अधिनियम के से, संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर मामलों धारा निपटने के लिए विधायी क्षमता का अभाव होगा, जैधारा कि सरफेसी अधिनियम। अपीलार्थियों अपीलार्थियों की ओर से **इरशाद हुसैन** पर रखी अवलम्ब भी गलत है।

46. संसद को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों धारा अवगत होना चाहिए जब उसने धारा 14 और धारा 14 (1-1) के प्रावधानों को अधिनियमित किया था।क) सरफेसी अधिनियम की धारा; और, यदि वह जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को ऐसी शक्ति प्रदान करने का इरादा रखता है, तो उसने प्रावधान में ही ऐसा निर्दिष्ट किया होगा।अधिनियमों के प्रावधान, जैधारा कि दंड प्रक्रिया संहिता या U.P। भूमि राजस्व अधिनियम पर यह यह तर्क देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि धारा 14 (1) में निर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल होगा।चूंकि धारा 14 (1) के पहले परंतुक के से किए गए आवेदन पर आदेश पारित करने की शक्ति संसद द्वारा दूसरे परंतुक के संदर्भ में मात्र जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट Cr.P.C के से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से मामलों धारा निपटने के लिए अधिकृत करना, सरफेसी अधिनियम में किसी भी प्रावधान की की अनुपस्थिति में में उधारा ऐसा करने की शक्ति प्रदान करना।

47. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 47** में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 प्रक्रियात्मक प्रकृति प्रकृति की है, और उसमें निर्धारित प्रक्रिया सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की सहायता लेने में सक्षम बनाती है; धारा 14 मात्र अधिकारियों को धारा 14 के से विचार की की गई प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने का अधिकार देती है, लेकिन लेकिन जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी सुरक्षित संपत्ति द्वारा संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति नहीं देती है; अधिनियम की धारा 14 का परंतुक जिला मजिस्ट्रेट को सुरक्षित संपत्ति के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय लेने लेने और निर्णय लेने का प्राइवेट लिमिटेड नहीं देता है; और इसी तरह का विचार बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खण्ड पीठ द्वारा लिया गया था।

48. **मनसा सिंथेटिक प्रा. लि. प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 49**, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के

के लिए बाध्य हैं, और अधिनियम की धारा 14 के से सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता या औचित्य औचित्य के सवाल पर निर्णय लेने के लिए सशक्त नहीं हैं।

49. न्यायाधीशों के अवलोकन को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, न ही अधिनियम के प्रावधानों के रूप में।टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं।**(मेसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य अन्य 15; श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स 50**)।न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं।वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं।(**हैरिंगटन 51; मेसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य 15**)। **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 47** में बॉम्बे उच्च न्यायालय और **मनसा सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड Ltd.49** में गुजरात उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। को संदर्भ धारा बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है, या इधारा एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को शामिल करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में "जिला मजिस्ट्रेट" शब्दों की आवश्यकता के रूप में में नहीं समझा जा सकता है।

50. सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 3 (32) "मजिस्ट्रेट" को परिभाषित करती है, जिसमें उस समय लागू दंड प्रक्रिया संहिता के से मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाता है।दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के से मजिस्ट्रेट की शक्तियों में सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां शामिल नहीं होंगी। इसलिए, सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3 (32) का का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

51. आइए अब हम उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों ध्यान दें दें जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, जिधारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) में संदर्भित किया गया है, में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होगा या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट शब्दों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होगा।के अरोकियाराज 1 3 3 में, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि सरफेसी अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया किया गया था; विधायिका इस तथ्य धारा अवगत थी कि गैर-महानगर क्षेत्रों में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्रों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं; यदि संसद का इरादा गैर-महानगर क्षेत्रों में भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करना था, तो इधारा धारा 14 में ही विशेष रूप धारा कहा जाना चाहिए था; विधायिका ने जानबूझकर, गैर-महानगर क्षेत्रों में सुरक्षित लेनदारों को सहायता देने के लिए धारा 14 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं किया है; उक्त विचार बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा इंडसइंड बैंक में लिया गया था।

52. **असीना14** में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 14 अनिवार्य करती है कि बैंक सहायता के लिए मात्र जिला जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धारा संपर्क कर सकता है, और जिला मजिस्ट्रेट कार्य सौंपने के लिए अधिकृत नहीं है और वह आदेश पारित करने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट को मामला नहीं दे सकता है; एक प्रतिनिधि, बिना बिना अधिकार के, अग्रेतर प्रतिनिधि नहीं कर सकता है; और जिला मजिस्ट्रेट को मामले को उठाना होगा और कानून के अनुसार आदेश पारित करना होगा।

53. **अरूपेश्वर चटर्जी और अन्य 10** में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 के से कब्जा करने का ठोस निर्णय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाना चाहिए; इस विचार को उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा किया गया था जिसमें कहा गया है कि, एक अधिकृत अधिकारी धारा एक शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद और सामग्री के बारे

बारे में खुद को संतुष्ट करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट "सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य धारा उपयुक्त पारित करेगा"; और इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी करने के पश्चात सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए, वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को उप-धारा (1ए) के से कब्जा करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

54. जिला मजिस्ट्रेट धारा संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 10 और उसकी उप-धारा (1) के से, प्रत्येक प्रत्येक जिले में, प्रेसीडेंसी-कस्बों के बाहर, स्थानीय सरकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगी, जिधारा जिला मजिस्ट्रेट कहा जाएगा।धारा 10 (2) ने स्थानीय सरकार को प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को छह महीने धारा अधिक अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने में सक्षम बनाया और ऐधारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के से जिला मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जो स्थानीय सरकार निर्देशित **हरि चंद अग्रवाल 2** में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिधारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 10 (2) के से जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों के साथ निवेश किया गया था, भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29 (1) के से एक आदेश दे सकता है, जिसमें बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड धारा संबंधित एक दुकान की मांग की गई थी, और जो एक किरायेदार के रूप में अपीलकर्ता के कब्जे में थी। थी। भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लिखित आदेश द्वारा धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी भी अचल सम्पति का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है।भारत रक्षा अधिनियम की धारा 40 ने प्रत्यायोजन की शक्ति निर्धारित की, और धारा 40 (1) इस प्रकार हैः

> "केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि कोई भी शक्ति या कर्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के से बनाए गए किसी नियम द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान या अधिरोपित किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के से, यदि कोई हो, जो निर्देश में निर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा।
>
> (क) केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, या
>
> (ख) क्या शक्ति या कर्तव्य किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल विधानमंडल को किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसी सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण प्राधिकरण द्वारा, या (ग) किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कानून बनाने की शक्ति है या नहीं।
>
> (2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि कोई भी शक्ति या कर्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के से बनाए गए किसी नियम द्वारा प्रदत्त या प्रदत्त किया गया है।राज्य सरकार पर अधिरोपित या जो इस अधिनियम या केंद्र सरकार पर प्रदत्त या अधिरोपित किसी ऐसे नियम के कारण, उप-धारा (1) धारा (1) के से राज्य सरकार द्वारा प्रयोग या निर्वहन का निर्देश दिया गया है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के से, जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाएं, किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा जो (केंद्र शासित प्रदेश के मामले को छोड़कर) केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण नहीं है। "
>
> है। "

55. भारत रक्षा अधिनियम की धारा 40 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिनियम धारा 29 के से अपनी शक्तियों को राज्य के सभी कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और उपायुक्तों को सौंपते हुए एक जारी की।बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किराया नियंत्रक, बटाला के समक्ष श्री हरि चंद अग्रवाल को बाहर निकालने निकालने के लिए एक आवेदन दायर किया और उसके बाद, श्रम आयुक्त के कहने पर दुकान की मांग करने के उपकरण का सहारा लिया, जिन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को लिखा कि एक सहकारी उपभोक्ता दुकान की स्थापना के लिए दुकान की आवश्यकता थी।

24 मार्च, 1964 को, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 29 के से कथित रूप धारा एक माँग आदेश जारी प्रश्नया, जिसमें दुकान की माँग की गई और श्री अग्रवाल को उसका कब्जा देने का निर्देश दिया गया।श्री अग्रवाल ने इस मांग आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 40 (1) के से जारी की गई अधिसूचना, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को धारा 29 के से केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था, अवैध और अमान्य थी।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट माँग आदेश देने के लिए सक्षम था क्योंकि उधारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (2) के से जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था।परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई।

56. श्री अग्रवाल द्वारा इसके विरुद्ध पुनः अपील करने पर, उच्चतम न्यायालय ने श्री अग्रवाल द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिट याचिका में आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए कहाः-

> ''.. .. .यह सर्वविदित है कि एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट को उसके कुछ कर्तव्यों से मुक्त करना है और वह उप-अनुभागों में निर्दिष्ट सीमा तक जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है।(3) में से।10. यह समान रूप से सर्वविदित है कि जिला मजिस्ट्रेट जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर है और वहां कार्यपालिका का प्रमुख है और वह जिले के अन्य मजिस्ट्रेटों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करता है।दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा उन्हें जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके अलावा जिला मजिस्ट्रेट भी हैं।राजस्व कानूनों के उद्देश्यों के लिए कलेक्टर के रूप में जाना जाता है।उन्हें कुछ राज्यों में कलेक्टर और अन्य राज्यों में उपायुक्त कहा जाता है।अंडरवर्ल्ड।संहिता की धारा 11 जब भी जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली होने के परिणामस्वरूप, जिले के मुख्य कार्यकारी प्रशासन में अस्थायी रूप से आने वाला कोई भी अधिकारी, ऐसा अधिकारी भी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और लगाए गए सभी कर्तव्यों का पालन करता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसा कि पहले देखा गया है, इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि राज्य सरकार कोई निर्देश देती है।संहिता के 10 (2) के अंतर्गत एक अधिकारी भी आता है जो अस्थायी रूप से जिले के मुख्य कार्यकारी प्रशासन का नेतृत्व करता है।11, जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है।संहिता की धारा 10 की योजना इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दो अलग-अलग और अलग-अलग प्राधिकरण हैं और भले ही बाद वाले को उप-धाराओं के से सशक्त किया जा सकता है।(2) जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, लेकिन तर्क के किसी भी विस्तार से एक अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नहीं कहा जा सकता है जो धारा 10 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द हैं।
>
> .. .. .. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से दो आधारों पर उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है, जिसके लिए उन्होंने प्रभुलाल रामलाल काबरा बनाम सम्राट मामले में नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन मांगा है।उस मामले में रायपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारत रक्षा नियमों के नियम 26 के से एक आदेश दिया गया था जिसमें भरतचंद्र काबरा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था।उस नियम ने केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार को हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान की, लेकिन प्रतिनिधि मंडल से संबंधित प्रावधानों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट को प्रांतीय सरकार द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग का अधिकार दिया गया था।हिरासत का आदेश देने वाले अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियां प्रदान गई थीं।10 (2) करोड़। पं. कोड लगभग उसी तरह के शब्दों में है जो वर्तमान मामले में पाए जाते हैं।दूसरे शब्दों में वह संहिता के से या उस समय लागू किसी अन्य कानून के से जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग सकता था।नागपुर अदालत के समक्ष दो मुद्दे उठाए गए थे; पहला यह था कि "किसी अन्य कानून" में "कानून" शब्द आता है।इंस।संहिता के 10 (2) का उद्देश्य एक कार्यकारी आदेश को शामिल करना नहीं था, बल्कि मात्र

विधायी अधिनियमों और नियमों, विनियमों या आदेशों को शामिल करना था जो कानून के बल पर थे।दूसरा यह था था कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए विशेष कानून थे कानून थे और उन्होंने कार्यपालिका को असाधारण और कठोर शक्तियां प्रदान कीं और ठीक इसी कारण से यह अनिवार्य था कि उन शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व की भावना के साथ और एक निश्चित स्थिति और अनुभव के अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इसलिए, उस शक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया था।ये दोनों दलीलें नागपुर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रबल रहीं और यह अभिनिर्धारित किया गया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट केवल अधिसूचना के आधार पर भारत रक्षा नियमों के नियम 26 के से शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (2)।

.. .. नागपुर निर्णय में पहले बिंदु पर एक विस्तृत चर्चा है, लेकिन इसकी शुद्धता की जांच करना पूरी तरह से अनावश्यक है क्योंकि हमारी मत है कि दूसरे बिंदु के निर्धारण के समर्थन में दिए गए अधिकांश कारण स्पष्ट और ठोस हैं और उन्हें सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।इन कारणों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः (i) हिरासत के मामले में सरकार को बहुत व्यापक, लगभग निरंकुश शक्तियां प्रदान की जाती हैं और इसलिए उनका उपयोग एक निश्चित स्थिति और अनुभव वाले अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व और सावधानी की उचित भावना के साथ किया जाना चाहिए; (ii) जब सरकार अपनी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण को सौंपती है, तो यह मान लेना अनुचित नहीं है कि वह प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधिमंडल के संबंध में आदेश देने से पहले प्रतिनिधि की योग्यता पर पूरी तरह से विचार करती हैः(iii) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिसे जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निवेशित किया जाता है, वह इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त नहीं करता है क्योंकि जिले में मात्र एक व्यक्ति हो सकता है जो जिला मजिस्ट्रेट सकता है और (iv) सरकार जब जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करती है तो उसे वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट का पद धारण करने वाले अधिकारी को प्रदान किया जाता है और कोई और नहीं।

.....वर्तमान मामले में "जिला मजिस्ट्रेट" शब्दों को संभवतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और यह मात्र नीचे जारी अधिसूचना का सहारा लेकर किया गया है।संहिता की धारा 10 (2) (2) जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।नागपुर न्यायालय में जो कारण प्रचलित थे और जिन्हें पहले ही पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया किया जा चुका है, वे इस विपरीत विचार को पूरा करते हैं कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को इसके तहत कार्य करने करने के लिए सक्षम माना जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 29 भले ही नागपुर का मामला हिरासत का था.....

57. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में, **हरि चंद अग्रवाल 2** में, यह स्पष्ट है कि चूंकि संसद ने मात्र जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की है, इसलिए यह मान लेना अनुचित नहीं है कि उसने इन अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने धारा पहले उनकी योग्यता पर विचार किया है; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिधारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के से जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, इस प्रकार सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के दूसरे परंतुक के से शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त नहीं करता है; संसद, जब उसने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की, तो उसका उद्देश्य मात्र पद धारण करने अधिकारी को ऐसी शक्ति प्रदान करना था, और कोई और नहीं; और शब्द "जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मजिस्ट्रेट"।

VII. क्या एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के से वैकल्पिक उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के से क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक बाधा हैः

58. अपीलार्थी-बैंक की ओर धारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश थपलियाल प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यर्थी-लिखित लिखित याचिकाकर्ता के पास सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के से ऋण वसूली न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को लागू आदेश आदेश का पर्याप्त और प्रभावी वैकल्पिक उपाय था; भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के से सामान्य रूप धारा राहत धारा इनकार विद्वान जाएगा यदि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है **(साधना लोध 53; सूर्य देव राय 54; संबद्ध रासायनिक प्रयोगशालाएं 55; कनैयालाल लालचंद 7)**; सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से कार्रवाई, धारा 13 (4) के चरण के पश्चात की गई कार्रवाई है, और इसलिए यह दायरे में आएगी।

59. दूसरी ओर, श्री A.K। प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता बंसल प्रस्तुत करेंगे कि किसी अन्य प्राधिकरण या न्यायालय की इस तरह के निर्णय की जांच करने की शक्ति को छोड़कर किसी प्राधिकरण के निर्णय को अंतिम रूप देने वाले वैधानिक प्रावधान, उच्च न्यायालय के लिए संविधान द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में बाधा नहीं होंगे, क्योंकि एक वैधानिक प्रावधान संविधान द्वारा निहित शक्ति को नहीं छीन सकता है **(हर्षद गोवर्धन 1 6; कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी 57)**; मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय को किसी भी पीड़ित पक्ष पक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है; और, यदि ऐसी चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की जांच कर सकता है, जैसा कि मामला है।**(कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी 57; हर्षद गोवर्धन सोंडागर 16)**।

60. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के से उच्च न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना **(एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 58)** का हिस्सा है।चूँकि ऐसी शक्ति को संविधान में संशोधन द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, कोई भी वैधानिक प्रावधान, पूर्ण या अधीनस्थ, ऐसी शक्ति के प्रयोग को सीमित या कम कम नहीं कर सकता है।जबकि यह न्यायालय, सामान्य रूप से, प्रतिबंध का प्रयोग करेगा और हस्तक्षेप करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के से अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा, जहां याचिकाकर्ता के पास पास एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय है, इस स्व-लागू सीमा के अपवाद हैं, और यह न्यायालय तब हस्तक्षेप करेगा, एक वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के बावजूद।ऐसे अपवादों में से एक यह है कि रिट याचिका में आक्षेपित आदेश, क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार **(व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन59)** की अंतर्निहित कमी से ग्रस्त है।वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता ने ने इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास विवादित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।इसके अग्रेतर जैसा कि **हर्षद गोवर्धन सोंडागर 16** में कहा गया है, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के से एक निर्णय को हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग विद्वान है विवेकाधिकार के इस तरह के प्रयोग को, आम तौर पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के से एक अंतर-न्यायालय अपील में बाधित नहीं किया जाएगा।इसलिए हम अपीलीय स्तर पर, प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता को सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के से ऋण वसूली न्यायाधिकरण धारा संपर्क करने के उपाय के लिए हटाने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

VIII. क्या बाद की कार्यवाही को किसी चुनौती की अनुपस्थिति में में भी अमान्य घोषित किया जा सकता हैः

61. जबकि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दिनांक 15.01.2018 के आदेश के पक्ष में रखे जाने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी की कार्रवाई, इस तरह के आदेश के संरक्षण के से 22.05.2018 पर विषय परिसर का कब्जा लेने में, भी पक्ष में रखे जाने की आवश्यकता होगी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील के से आदेश में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दिनांक 15.01.2018 के आदेश के बाद, बैंक द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को भी अमान्य घोषित कर दिया है।जबकि हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई मत से सहमत हैं कि विषय सम्पति उस स्थिति में बहाल होने के लिए उत्तरदायी है

जो दिनांकित आईडी2 पारित होने से पहले थी, हम यह स्पष्ट करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का अपीलकर्ता-बैंक द्वारा आईडी1 पर की गई नीलामी पर बैंक द्वारा जारी बिक्री सूचना के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इसका नीलामी खरीदार द्वारा भुगतान की गई बोली राशि के आईडी3 पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

62. प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने सम्पति की नीलामी में अपीलकर्ता-बैंक की कार्रवाई को चुनौती देने का विकल्प भी भी नहीं चुना है।भले ही प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता का विचार था कि अपीलकर्ता-बैंक की कार्रवाई, बिक्री सूचना के अनुसार अनुसार विषय सम्पति को नीलामी में डालने में, अवैध मात्र, गैरकानूनी कार्रवाई का विरोध करने का एकमात्र तरीका कानून कानून का सहारा लेना था।एक आदेश, भले ही सद्भावना से नहीं किया गया हो, फिर भी एक ऐसा कार्य है जो कानूनी परिणामों में सक्षम है।इसके माथे पर अयोग्यता का कोई निशान नहीं है। जब तक आवश्यक इसे रद्द या अन्यथा परेशान नहीं करता है, तब तक यह अपने स्पष्ट उद्देश्य के लिए, आदेशों में सबसे त्रुटिहीन के रूप में प्रभावी रहेगा।प्रशासनिक व्यवस्था में **वेड और फोर्सिथ, सेवेंथ एडन., 1994; स्मिथ बनाम ईस्ट एलो रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 60, एफ. हॉफमैन-ला रोश एंड कंपनी 61 एम. के. कुन्हीकन्नन नाम्बियार मंजेरी मनिकोथ 63)**।किसी भी आदेश/कार्यवाही को तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है कि यह अवैध, अमान्य या कानून के अनुरूप नहीं है।यह सिद्धान्त समान रूप से सच है, भले ही 'अयोग्यता' का ब्रांड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होःक्योंकि वहाँ मात्र न्यायालय के निर्णय को प्राप्त करके ही कानून में आदेश का प्रभावी ढंग से विरोध किया जा सकता है।**(पुणे नगर निगम 64**)।यहां तक कि अगर आदेश/कार्यवाही अमान्य/अमान्य है, तो पीड़ित पक्ष यह निर्णय नहीं ले सकता है कि उक्त आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं है।उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और ऐसी घोषणा की मांग करनी चाहिए।आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है और फिर भी, भले ही इसकी अयोग्यता को किसी दी गई गई परिस्थिति में अदालत के समक्ष चुनौती दी गई हो, अदालत याचिकाकर्ता की स्थिति या विलम्ब के आधार या छूट के सिद्धांत या किसी अन्य कानूनी कारण सहित विभिन्न आधारों पर इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है।आदेश एक उद्देश्य के लिए या एक व्यक्ति के लिए शून्य हो सकता है, यह दूसरे उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता है।**(कृष्णादेवी मालचंद कामठिया & Ors.65; पोर्ट ऑफ कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल 66, पुणे नगर निगम64; गुरदेव सिंह 67; आर. थिरुविरकोलम 68; M.K. कुन्हीकन्नन नाम्बियार मंजेरी मनिकोथ नडूविल 63** .और **तैयबभाई एम. बागसरवाला और अन्य69)**।चूंकि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने नीलामी की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है, है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को, जिस सीमा तक ऐसी कार्यवाही को भी अमान्य घोषित किया विद्वान है, अपास्त दिया जाता है।यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने विषय सम्पति की नीलामी करने में अपीलकर्ता-बैंक की कार्रवाई की पुष्टि की है।हमने केवल इतना माना है कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती की अनुपस्थिति में में उक्त कार्यवाही को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था।हम यह स्पष्ट करते हैं कि अब हमारे द्वारा पारित आदेश नहीं करेगा। अयोग्यता के कारण को स्थापित करने के लिए कानून में कार्यवाही की जाती है और प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता को उचित कानूनी कार्यवाही में उक्त नीलामी की कार्यवाही पर सवाल उठाने से रोका जाता है और यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो सक्षम अदालत/न्यायाधिकरण इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित, इसके गुण-गुण-दोष पर आग्रह किए गए तर्कों की जांच करेगा।

IX. निष्कर्षः

63. ऊपर उल्लिखित सीमित सीमा को छोड़कर, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाती है।विशेष अपील आंशिक रूप से पूष्ट कि जाती है, और परिस्थितियों में, बिना किसी खर्चे के आंशिक रूप से खारिज की जाती है।

(लोक पाल सिंह, जे.) **(रमेश रंगनाथन, C.J)**

10.01.2019 10.01.2019

राहुल